अमित शाह 13 को जयपुर में कलैक्टर -एसपी कॉन्फ्रैंस में भी भाग लेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की

जयपुर, 9 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित जयपुर दौरे (13 अक्टूबर) की तैयारियों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के बाद, आपराधिक न्याय प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आया है। इन तीन नवीन कानूनों के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित होने वाली छह दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे।

शर्मा ने कहा कि इस अवसर पर केन्द्रीय गृहमंत्री "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024" के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग के साथ ही, विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही, प्रदेश के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी राशि का हस्तान्तरण तथा 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारम्भ किया जाएगा। एफ.एस.एल. हेतु वाहनों एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धी पेट्रोलिंग की स्कूटियों एवं मोटरसाइकिलों का फ्लैगऑफ भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित जयपुर दौरे की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 13 अक्टूबर से जयपुर में जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेन्स का आयोजन करने जा रही है।

- **गृह मंत्री अमित शाह जयपुर प्रवास के दौरान तीन नये कानून के एक वर्ष पूर्ण होने पर सीतापुर में आयोजित 6 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे तथा राइज़िंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग, दूध सब्सिडी की राशि का हस्तांतरण भी करेंगे।**

इस दौरान कानून व्यवस्था, भूप्रबंधन, सुशासन, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेन्स के उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय गृहमंत्री भी शामिल होंगे।

इस दौरान, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बिहार की एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सूची को एक समेकित रूप में जारी करने के बजाय, 90,000 अलग-अलग इमेज फाइलों में जारी किया है। कांग्रेस का सवाल है - चुनाव आयोग मतदाता सूची को विश्लेषण के लिए सुगम बनाने में क्यों हिचक रहा है? आखिर उसे डर किस बात का है?

कांग्रेस पार्टी ने बिहार मतदाता सूची के प्रारंभिक विश्लेषण के बाद ईसीआई से नीचे दिए गए सवाल पूछे हैं -

1. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार में 7.72 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। अब विधानसभा चुनावों के लिए यह संख्या घटकर 7.42 करोड़ रह गई है, यानी लगभग 30 लाख मतदाता सूची से गायब हैं।

ये 30 लाख लोग कौन हैं?

इनमें से कितने लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया था?

2. ईसीआई का दावा है कि 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए, लेकिन फॉर्म 6 केवल 16.93 लाख के लिए उपलब्ध है।

बाकी 4.6 लाख फॉर्म कहाँ हैं?

क्या इन मतदाताओं को बिना उचित प्रक्रिया के जोड़ा गया?

3. एसआईआर प्रक्रिया के तहत कुल 67.3 लाख मतदाताओं को हटाया गया, जिनमें से एक-दसवां हिस्सा सिर्फ 15 विधानसभा क्षेत्रों में ही है। चुनाव आयोग ने अब तक सभी हटाए गए मतदाताओं की अंतिम सूची (बूथ व कैटगरी अनुसार) क्यों सार्वजनिक नहीं की?

4. कांग्रेस के विश्लेषण के अनुसार, अंतिम प्रकाशित सूची में अब भी 5 लाख से अधिक डुप्लिकेट मतदाता (जिनका नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र, लिंग और पता समान है) मौजूद हैं।

जब इतने डुप्लिकेट अब भी हैं, तो एसआईआर का उद्देश्य क्या था?

अब आयोग इन्हें सत्यापित और साफ कैसे करेगा?

कांग्रेस ने यह भी कहा कि सीईसी ने यह अनुमति दी है कि नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक ही नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। इसके बाद मतदाता सूची को फ्रीज़ किया जाना चाहिए, और किसी भी पूरक सूची से मूल मतदाता आधार में बदलाव नहीं होना चाहिए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची में अनियमितताओं और इसके जरिए चुनावी परिणामों में कथित हेरफेर की ओर इशारा करते रहे हैं। पार्टी ने मतदाता सूचियों को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के सभी प्रयासों का स्वागत किया है।

कांग्रेस का कहना है कि ऊपर दिए गए सवालों के स्पष्ट उत्तर देना चुनाव आयोग के लिए जनता का भरोसा जीतने और मतदाता सूची की साख व पारदर्शिता साबित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

'हर परिवार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नौकरी पाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार बनने के 20 दिनों के अन्दर विधेयक (कानून) लाया जाएगा। उन्होंने कहा, "बिहार में ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जिसमें नौकरी न हो।"

तेजस्वी ने कहा, "हम आज एक ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं। बहुत से लोग जानना चाहते थे कि हम बिहार को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। बीते 20 वर्षों में इस जर्जर सरकार ने कभी यह महसूस ही नहीं किया कि बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है।" उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दल -जेडीयू और भाजपा नौकरियों का वादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, बिहार का कोई भी परिवार जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उसे एक नई विधायी व्यवस्था के तहत नौकरी दी जाएगी। सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर यह कानून लाया जाएगा, और 20 महीनों के भीतर हम सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में कोई ऐसा घर न बचे जिसमें सरकारी नौकरी न हो।

एसएमएस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एसएमएस अस्पताल के एचओडी डॉ. मनीष अग्रवाल के खिलाफ परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी कि वह न्यूरो सर्जरी विभाग में काम आने वाले ब्रेन कॉइल सप्लाई करता है। लेकिन डॉ. मनीष अग्रवाल इनके बिलों पर काउंटर सिग्नेचर करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन करवाया, जिसमें शिकायत सच पाई गई। फिर एचओडी डॉ. मनीष अग्रवाल को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया और गुरुवार की देर शाम डॉ मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपये रिश्वत लेते ट्रैप किया गया।

'अपने सामान के साथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि जैसे-जैसे शटडाउन लंबा खिंचता है तो समयपालन (पंक्चुअलिटी) प्रभावित हो सकती है। ओएजी एविएशन के वरिष्ठ विश्लेषक जॉन ग्रांट कहते हैं, "हवाई यातायात सटीकता और मनोबल पर चलता है। अनिश्चितता और बिना वेतन पर दक्षता बनाए नहीं रखी जा सकती।"

क्रूज़ यात्रा पर अभी तक इसका असर अपेक्षाकृत कम है। तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) और सीमा शुल्क एजेंट जैसे जरूरी संघीय कर्मचारी काम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें भी वेतन नहीं मिल रहा। लेकिन अगर यह गतिरोध लंबा चला, तो बंदरगाहों और सीमा शुल्क संचालन पर भी असर पड़ सकता है।

जमीन पर स्थिति और भी खराब है। अमेरिका के नैशनल पार्क, जो आमतौर पर पतझड़ के मौसम में पर्यटकों से भरे रहते हैं, अब प्रशासनिक जड़ता में फंसे हुए हैं। योसेमाइट, यैलो स्टोन, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे स्थान खुले तो हैं, लेकिन वहां के विज़िटर सैंटर, शौचालय और स्मारक जैसे सुविधायें बंद हैं। नेशनल पार्क सर्विस (एनपीएस) ने लगभग 64 प्रतिशत कर्मचारियों - यानी करीब 9,300 लोगों - को अवैतनिक अवकाश पर भेज दिया है, जिससे कई पार्क बिना निगरानी के रह गए हैं।

नेशनल पार्क्स कंज़र्वेशन एसोसिएशन (एनपीसीए) ने चेताया है कि स्थिति खतरनाक हो रही है। एनपीसीए की अध्यक्ष थेरेसा पिएर्नो कहती हैं, "ग्रेट फॉल्स में आगंतुकों ने अवैध रूप से गाड़ियाँ पार्क कीं और अंदर जाने के लिए बैरिकेड्स लांघे। गेटवे में भीड़ समुद्र तटों पर उमड़ पड़ी जबकि वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था - यह गंभीर सुरक्षा जोखिम है।" उन्होंने कहा कि पार्कों पर दबाव बढ़ रहा है और इस शटडाउन को उन्होंने "नैशनल पार्क्स के सिस्टम्स के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक" बताया।

शहरी यात्रियों को भी राहत नहीं है। वॉशिंगटन डी.सी. में पर्यटकों को नेशनल आर्काइव्स, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और लाइब्रेरी ऑफ कॉन्ग्रेस जैसी जगहों से वापस भेजा जा रहा है, जो अनिश्चितकाल के लिए बंद हैं। एक ब्रिटिश यात्री ने रैडिट पर लिखा, "हम लंदन से "डिक्लेरेशन ऑफ इनडिपैस" देखने आए थे, लेकिन अब अंदर जा ही नहीं सकते।"

फिर भी सांस्कृतिक जीवन पूरी तरह ठप नहीं हुआ है। जॉन एफ. कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे थिएटर और संगीत हॉल अभी भी सीमित स्टाफ के साथ कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं - जो लोगों के लिए इस असामान्य माहौल में सामान्यता की एक झलक है।

इस बीच, वीज़ा स्वीकृति या आप्रवासन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे विदेशी यात्रियों को नई अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल ने चेतावनी दी है कि दूतावासों में सीमित स्टाफ के कारण आवेदनों में हफ्तों की देरी हो सकती है। बयान में कहा गया, "जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन लंबी प्रतीक्षा की उम्मीद करें।"

फिलहाल अधिकांश उड़ानें संचालित हो रही हैं और क्रूज़ जहाज रवाना हो रहे हैं। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि असली चिंता साख की है। एटमॉस्फीयर रिसर्च ग्रुप के यात्रा अर्थशास्त्री हेनरी हार्टवेल्ड कहते हैं, "हर दिन जब यह शटडाउन जारी रहता है, यह अमेरिका की एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में छवि को थोड़ा और कमजोर कर देता है -चाहे वह व्यापारिक यात्रा हो या पर्यटन।" राजनीतिक गतिरोध जारी रहने के बीच यात्रियों के लिए संदेश स्पष्ट है - सिर्फ पासपोर्ट नहीं, धैर्य भी साथ रखें।

दो साल की बेरहम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोनों जगहों पर लोगों ने स्वत: जश्न मनाना शुरु कर दिया। हमले के बाद दो वर्षों तक, उन्होंने अमानवीय हालात और अपने प्रियजनों की मौतों का गहरा दुख झेला है।

यहाँ तक कि गाज़ा की जनता भी हमास आतंकवादियों के कर्मों की भारी कीमत चुका कर थक चुकी है। अरब आबादी का एक बड़ा हिस्सा युद्ध की भयंकर मानवीय और आर्थिक कीमत चुकाए जाने से दुखी था और अब वो शांति और बंधकों की रिहाई की कामना कर रहा था।

समग्र वापसी (ओवर ऑल डिस्एंगेजमैंट) के विभिन्न विवरणों पर, वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कई प्रमुख अरब तथा मुस्लिम देशों के सक्रिय मार्गदर्शन में काम चल रहा है।

शांति वार्ताएं मुख्य रूप से मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुईं, जो इज़रायल की सीमा पर स्थित है। तुर्की ने भी इन वार्ताओं में सक्रिय भागीदारी की और संघर्षविराम तथा जमीनी क्रियान्वयन की निगरानी करने की इच्छा जताई।

इससे जुड़ा एक सवाल कई लोगों के मन में घूम रहा है, जिनमें कुछ शीर्ष इज़रायली नेता भी शामिल हैं और वे इस उपलब्धि के लिए डॉनल्ड ट्रंप को खुश करने के उत्सुक हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या इज़रायल-गाज़ा शांति से डॉनल्ड ट्रंप को राजनीतिक लाभ मिलेगा? क्या यह उपलब्धि उन्हें राजनीतिक वरदान देगी? इस पर कई हलकों में चर्चा जारी है।

बंगाल में भी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिलेगी। तकनीकी साधनों के उपयोग का निर्णय इसलिए भी लिया गया है क्योंकि स्कूल शिक्षक, जिन्हें बीएलओ के रूप में भी नियुक्त किया जाता है, अत्यधिक कार्यभार से परेशान हैं। स्कूल छ: दिन चलते हैं, तथा बहुत से शिक्षकों को लम्बी दूरी तय करके स्कूल आकर शिक्षण कार्य करना होता है। इसलिये अपनी शिक्षण जिम्मेदारियों के साथ-साथ, घर-घर जाकर एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने में शिक्षकों ने कठिनाई जताई है। बहुत से शिक्षकों ने आयोग से अनुरोध किया है कि उन्हें एक महीने का अवकाश दिया जाए, ताकि वे चुनाव संबंधी कार्य पूरी कुशलता से पूरा कर सकें। प्रक्रिया की तैयारी के तहत, आज कोलाघाट में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें पूर्व मेदिनीपुर, बांकुरा और झाड़ग्राम जिलों के बीएलओ, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) और सहायक ईआरओ शामिल हुए।

सीजेआई पर हमला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रॉक्सिमिटी एक्सेस कार्ड तुरंत रद्द किया जाए। सूत्रों के अनुसार, 71 वर्षीय वकील के खिलाफ फौजदारी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की अनुमति लेने हेतु अटॉर्नी जनरल को पत्र भेजा गया है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी राकेश किशोर को निलंबित कर दिया है।

किशोर, जिन्होंने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक सम्बद्धता या आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ने समाचार एजेंसी "एएनआई" को बताया कि उन्होंने यह कदम भावनात्मक पीड़ा के कारण उठाया, जो उनके अनुसार, हिंदू धार्मिक मामलों में "बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप" के चलते उत्पन्न हुई थी। उन्होंने अपने कृत्य पर कोई अफसोस व्यक्त नहीं किया।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908